



भारत में नेट न्यूट्रैल्टी

यह एडिटरियल 07/11/2023 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“A telco double dip attempt that threatens Net neutrality”](#) लेख पर आधारित है। इसमें नेट न्यूट्रैल्टी सदिधांतों को बनाए रखने के महत्त्व के बारे में चर्चा की गई है जो एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने में नहिती है जो नवाचार को प्रोत्साहित करता है, स्वस्थ प्रतस्पर्द्धा का पोषण करता है और उपभोक्ता कल्याण को प्राथमकता देता है।

प्रलिमिस के लिये:

[नेट न्यूट्रैल्टी](#), [भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण \(TRAI\)](#), [ओवर-द-टॉप \(OTT\) सेवा प्रदाता](#), [दूरसंचार सेवा प्रदाता \(TSP\)](#), कंटेंट डलिवरि नेटवर्क (CDN), फेसबुक की फ्री बेसकिंस, डेटा सेवाओं के लिये भेदभावपूर्ण शुल्कों का नषिध नयिम (2016), वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VOIP)।

मेन्स के लिये:

नेट न्यूट्रैल्टी का परचिय, नेट न्यूट्रैल्टी का महत्त्व, भारत में नेट न्यूट्रैल्टी की नियामक स्थिति, भारत में नेट न्यूट्रैल्टी पर मुख्य बहस, भारत में एक समावेशी डजिटल परदृश्य के लिये आगे की राह।

हाल ही में [भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण](#) (Telecom Regulatory Authority of India- TRAI) ने सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं के वनियमन पर परामर्श प्रक्रिया शुरू की।

दूरसंचार कंपनियों का तर्क है कि नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसी OTT सेवाओं को बैडवडिथ की लागत साझा करनी चाहिये क्योंकि वे दूरसंचार कंपनियों के बुनियादी ढाँचे से लाभ उठाते हैं। इस संदर्भ में नेट न्यूट्रैल्टी (Net Neutrality) की बहस एक बार फिर से उभर आई है।

नेट न्यूट्रैल्टी क्या है?

- [नेट न्यूट्रैल्टी](#) किसी भी मानदंड पर मध्यवर्ती नेटवर्क द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक में **भेदभाव न करने की अवधारणा** को संदर्भित करती है। नेटवर्क को इसके माध्यम से प्रसारित होने वाली सभी सूचनाओं के प्रतितस्थ होना चाहिये।
- **किसी नेटवर्क से गुजरने वाले सभी संचार (communication) को एक समान रूप से देखा जाना चाहिये**; अर्थात इसके कंटेंट, एप्लीकेशन, सेवा, डविाइस, प्रेषक या प्राप्तकर्ता पते (sender or recipient address) से स्वतंत्र होना चाहिये।
- नेट न्यूट्रैल्टी यह सुनिश्चित करती है कि हर किसी को **इंटरनेट पर सूचना और सेवाओं तक समान पहुँच** मिले, चाहे उनके वित्तीय संसाधन कुछ भी हों या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वेबसाइटों का आकार एवं शक्ति कुछ भी हो।
- **शब्द की उत्पत्ति:** 'नेट न्यूट्रैल्टी' शब्द को कोलंबिया लॉ स्कूल के प्रोफेसर **टिम वू (Tim Wu)** ने वर्ष 2003 में प्रकाशित अपने **'नेटवर्क न्यूट्रैल्टी, ब्रॉडबैंड डिसिंकरमिनिशन'** शीर्षक पेपर से लोकप्रिय बनाया था।
- नेट न्यूट्रैल्टी के प्रमुख सदिधांतों में शामिल हैं:

NO BLOCKING	Your internet access provider (IAP) cannot block you from accessing legal content of your choice.
NO THROTTLING	Your IAP cannot intentionally throttle legal internet traffic to slower speeds than other traffic.
NO PAID PRIORITIZATION	Your IAP cannot sell 'fast lane' service to content providers who can pay more than others.

- इंटरनेट क्षेत्र के जो हतिधारक नेट न्यूट्रैलिटी से प्रभावित होते हैं, उनमें शामिल हैं:
 - किसी भी इंटरनेट सेवा के उपभोक्ता
 - **दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSPs)** या इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs),
 - **ओवर-द-टॉप (OTT)** सेवा प्रदाता (वे जो वेबसाइट और एप्लीकेशन जैसी इंटरनेट एक्सेस सेवाएँ प्रदान करते हैं),
 - सरकार, जो इन खलिाड़ियों के बीच संबंधों को वनियमिति और परभाषति कर सकती है
 - साथ ही, ट्राई (TRAI) **दूरसंचार क्षेत्र में एक स्वतंत्र नयामक** है जो मुख्य रूप से TSPs और उनकी लाइसेंसिंग शर्तों आदि को वनियमिति करता है।

नेट न्यूट्रैलिटी क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **खुले इंटरनेट का संरक्षण:** नेट न्यूट्रैलिटी सूचना, वचारों और सेवाओं तक नशुलक एवं अपरतबिंधति पहुँच सुनशुचिति करती है।
 - नेट न्यूट्रैलिटी के अभाव में ISPs वशिश **कुछ वेबसाइटों को उच्च कनेक्शन गति** प्रदान कर सकते हैं, जबकि अन्य के लयि पहुँच को सीमति कर सकते हैं। चरम स्थति में कोई ISP कुछ कंटेंट तक पहुँच को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है।
- **उपभोक्ता वकिलप को बढावा:** नेट न्यूट्रैलिटी उपभोक्ताओं को बना किसी परतबिंध के उन कंटेंट, एप्लीकेशन और सेवाओं को स्वतंत्र रूप से चुनने की अनुमति देती है जनि तक वे पहुँच बनाना चाहते हैं। वे ISPs द्वारा नरिधारति पेशकशों के पूर्व-चयनति समूह तक सीमति नहीं रहते।
- **अभवि्यक्ता की स्वतंत्रता की रक्षा:** नेट न्यूट्रैलिटी लोगों को बना किसी हस्तक्षेप के संगठति होने, संवाद करने और समर्थकों को लामबंद करने की अनुमति देकर अभवि्यक्ता की स्वतंत्रता की रक्षा करती है, जसिसे यह लोकतांत्रकि संलग्नता के लयि एक महत्त्वपूर्ण साधन बन जाती है।
- **नवाचार को बढावा:** खुला इंटरनेट नवाचार और परतसिपर्द्धा को प्रोत्साहति करता है। स्टार्टअप, छोटे व्यवसायों और उद्यमयिों को ISPs के साथ कोई सौदा करने की आवशयकता के बना नई सेवाएँ शुरु करने और उपयोगकर्ताओं तक पहुँचने का समान अवसर उपलब्ध होता है।
- **परतसिपर्द्धा-वरीधी अभयासों पर रोक:** नेट न्यूट्रैलिटी के अभाव में ISPs अपने स्वयं के या भागीदारों के कंटेंट या सेवाओं का पक्षसमर्थन करते हुए परतसिपर्द्धा-वरीधी व्यवहार में संलग्न हो सकते हैं। नेट न्यूट्रैलिटी नयिम ऐसे भेदभावपूर्ण अभयासों पर रोक लगाते हैं और नषिपक्ष परतसिपर्द्धा बनाए रखते हैं।

Why Net Neutrality Must Be Protected



It won't cost websites or people extra money just to be able to go to a certain web location.



Without net neutrality, Internet Service Providers can discriminate against any website, group, or person they want.



Net neutrality allows small businesses to have a digital presence and let them compete without worrying if their ISP will cut off access to their website.



Net neutrality gives companies a fair and equal platform to compete on.



Immediately after net neutrality rules were placed, investments in companies went up by 5%.



It keeps the Internet equal and fair for everybody.

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी की नयामक स्थिति

भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधिकरण भारत में नेट न्यूट्रैलिटी को सुनिश्चित करने और इसे वनियमिती करने में एक केंद्रीय भूमिका का नरिवहन करता है। भारत में नेट न्यूट्रैलिटी का वनियमन वकिसाओं की नमिनलखिति शृंखला द्वारा चहिनति है:

■ एयरटेल ज़ीरो और VoIP वविाद (2014):

- वर्ष 2014 में भारती एयरटेल ने 'एयरटेल ज़ीरो' योजना शुरु की, जसिने ज़ीरो-रेटगि और नेट न्यूट्रैलिटी के संभावति उल्लंघनों के बारे में चतिाएँ बढा दी।
- स्काइप (Skype) और व्हाट्सएप (WhatsApp) जैसी वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल (VoIP) सेवाओं के लयि अतरिकित्त शुल्क वसूल करने के एयरटेल के कदम ने भी वविाद को जन्म दयि।

■ ट्राई का परामर्श पत्र (2015):

- वर्ष 2015 में ट्राई (TRAI) ने ओवर-द-टॉप (OTT) सेवाओं और नेट न्यूट्रैलिटी पर एक परामर्श पत्र जारी कयि जसिमें सार्वजनकि राय आमंत्रति की गई।

■ ट्राई के 2016 के वनियमन:

- वर्ष 2016 में ट्राई ने डेटा सेवाओं के लयि अलग-अलग दरों पर रोक लगाकर नेट न्यूट्रैलिटी के पकष में नरिणय दयि।
- ट्राई के 'डेटा सेवाओं के लयि भेदभावपूर्ण टैरफि का नषिध वनियमि, 2016' (Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations, 2016) ने गैर-भेदभावपूर्ण मूल्य नरिधारण सुनिश्चित करते हुए फेसबुक की 'फ्री बेसकिक्स' जैसी ज़ीरो-रेटगि सेवाओं को समाप्त कर दयि।

■ वर्ष 2017 में ट्राई की अनुशंसाएँ:

- ट्राई ने गैर-भेदभावपूर्ण सदिधांतों का वसितार कंटेंट वयवहार (content treatment) तक कयि।
- अनुशंसा की गई कि कंटेंट भेदभाव को रोकने के लयि सरकार और ISPs के बीच लाइसेंस समझौतों में संशोधन कयि जाना चाहयि।

■ 5G डजिटिल रूपांतरण पर ट्राई का परामर्श पत्र, 2023:

- इसका उद्देश्य नीतगित चुनौतयिों की पहचान करना और 5G पारतिंतर के भीतर नई प्रौद्योगकियिों के तीवर अंगीकरण और इष्टतम उपयोग के लयि एक प्रभावी ढाँचा तैयार करना है।

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर जारी बहस के प्रमुख वषिय

■ दूरसंचार कंपनयिों का परपिरेकष्य

◦ राजस्व में गरिवट:

- पछिले दस वर्षों में दूरसंचार कंपनयिों के राजस्व में कमी देखी गई है। ऐसा मुख्य रूप से वॉयस कॉल और SMS जैसी पारंपरकि सेवाओं से प्राप्त राजस्व के मामले में हुआ है।
- नशुलक प्रतसिपर्दधी OTT सेवाओं का प्रसार इस गरिवट का एक प्रमुख कारक रहा है।

◦ अवसंरचनात्मक उन्नतति:

- दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSPs) का तर्क है कि वे नेटवर्क अवसंरचना में पर्याप्त नविश करते हैं और इन नविशों को बनाए रखने तथा इंटरनेट पहुँच के वसितार को सुवधाजनक बनाने के लिये अलग-अलग मूल्य निर्धारण जैसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है।
- टेलीकॉम कंपनियों मानती हैं कि OTT प्लेटफॉर्म उनके द्वारा स्थापित और बनाए रखे गए अवसंरचना का उपयोग कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
 - इसलिये, ये कंपनियों नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, डज़िनी+ हॉटस्टार जैसे OTT कंटेंट प्रदाताओं से बैडविल्डिथ से जुड़े खर्चों में योगदान करने का आग्रह रखती हैं।
- कराधान में असमानता:
 - टेलीकॉम कंपनियों का तर्क है कि OTT सेवाओं को कराधान और लाइसेंसिंग शुल्क में असमानता का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप असंतुलित प्रतिस्पर्धी परदृश्य का निर्माण होता है।
- OTT प्लेटफॉर्मों का परिप्रेक्ष्य
 - इंटरनेट प्रदाताओं की वशिष्ट भूमिका :
 - OTT प्रदाता इस बात पर बल देते हैं कि दूरसंचार कंपनियों इंटरनेट पहुँच के लिये माध्यम के रूप में कार्य करती हैं कि उनके पास इसका स्वामित्व है। उपभोक्ता डेटा प्लान के माध्यम से पहुँच के लिये इन कंपनियों को शुल्क प्रदान करते हैं।
 - OTT सेवाओं के उपयोग से डेटा की खपत बढ़ती है, जिससे दूरसंचार कंपनियों की राजस्व वृद्धि में योगदान होता है।
 - नेट न्यूट्रैलिटी की मांग:
 - इंटरनेट वखंडन (internet fragmentation) को रोकने और समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये नेट न्यूट्रैलिटी अत्यंत आवश्यक है। यह TSPs के भेदभावपूर्ण व्यवहार—जो नवाचार को बाधित कर सकता है और छोटे पैमाने के एवं नवोन्मेषी OTT सेवाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकता है, पर रोक लगाती है।
 - नेट न्यूट्रैलिटी के समर्थक वचिारों एवं ज्ञान के लोकतांत्रिक आदान-प्रदान, नैतिक व्यावसायिक अभ्यासों, नषिपक्ष प्रतिस्पर्धा और जारी नवाचार के लिये एक स्वतंत्र, खुले एवं भेदभावरहित पूर्ण इंटरनेट बनाए रखने में वशिवास करते हैं।
 - कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क प्रावधान:
 - OTT प्लेटफॉर्म पहले से ही कंटेंट की डिलीवरी के लिये इंटरनेट की क्षमता को वृहत रूप से बढ़ाने के लिये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDNs) से संबंधित खर्चों को कवर कर रहे हैं।
 - OTT सेवाएँ कंटेंट की वविधता एवं गुणवत्ता, स्ट्रीमिंग गुणवत्ता, नेविगेशन की आसानी और डविाइस की उपलब्धता के आधार पर अपने स्वयं के बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का सामना करती हैं।
 - कीमतें बढ़ाने की दूरसंचार कंपनियों की स्वतंत्रता:
 - दूरसंचार कंपनियों लागत को कवर करने के लिये अपनी कीमतों को समायोजित कर सकती हैं, क्योंकि वे OTT कंटेंट एवं अवसंरचना नविश द्वारा सृजित मांग का लाभ उठाती हैं।
- उपभोक्ताओं के लिये चिंताएँ:
 - अतिरिक्त लागत :
 - नेट न्यूट्रैलिटी के समर्थकों का तर्क है कि OTT प्लेटफॉर्मों पर अतिरिक्त लागत का अधिपण ग्राहकों की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शुल्क या सेवा गुणवत्ता की कमी की स्थिति बन सकती है।
 - नेट न्यूट्रैलिटी के आलोचकों का तर्क है कि उपभोक्ताओं की पहुँच और पसंद/वकिल्प की सुरक्षा के लिये इंटरनेट सेवाओं में खुली प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

The big debate

SAYING YES TO NEUTRALITY



Neutral Internet services allow access to all the data available on the Web.



Neutrality also ensures that the access rights to a website are unbiased. This is highly beneficial for users who passively use the Internet for information access, to get their news, or for mere entertainment.



A pro-net neutrality decision also is said to benefit businesses and companies established on or revolving around the Internet. The hosting and maintenance of a business on the Web would be uniform for all enterprises availing the cyberspace.



Because net neutrality ensures equality for all content on the web, same exposure, standard quality, equal speed, and same revenue on the Web, a majority of the upcoming ISPs are also opting for net neutrality.

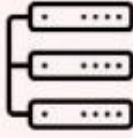
SAYING NO TO NEUTRALITY



The absence of net neutrality helps providers and the Internet architects in curbing questionable content on the Web and ensuring that all the websites get equal privileges.



In a controlled manner, the absence of net neutrality maintains the legality of the Internet.



Another favorable result from the security checks implemented on the Internet help in improving the infrastructure of the Web. With the illegal activities out of the way, the Internet will be left with more "room" for legal and productive establishments and enterprises.



An anti-net neutrality decision would also facilitate a drop in the number of free-loaders on the Internet.

भारत में समावेशी डिजिटल परदृश्य के लिये आगे की राह

- **वनियमन संबंधी स्पष्टता:** ट्राई को नेट न्यूट्रैलिटी पर नयामक स्पष्टता और मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखना चाहिये। इसमें नेट न्यूट्रैलिटी सदिधांतों को परभाषित करना और लागू करना शामिल है जो भेदभावपूर्ण अभ्यासों को रोकते हैं, साथ ही उचित नेटवर्क प्रबंधन की अनुमति भी देते हैं।
- **बहु-हतिधारक दृष्टिकोण:** एक संतुलित दृष्टिकोण पर वचार कथिा जाए जो दूरसंचार कंपनयिों और OTT सेवा प्रदाताओं दोनों के हतिों की पहचान करे। एक ऐसा मध्यम मार्ग ढूँढना अत्यंत आवश्यक है जो नषिपक्ष प्रतसिपरद्धा एवं नवाचार सुनशिचति करे, साथ ही दूरसंचार कंपनयिों को नविश पुनरप्राप्त की अनुमति दे।
- **पारदर्शति:** ISPs द्वारा अपने नेटवर्क प्रबंधन और OTT प्रदाताओं के साथ सहयोग के तरीकों में पारदर्शति को प्रोत्साहति कथिा जाए। यह पारदर्शति यह सुनशिचति करने में मदद कर सकती है ककिोई भी नेटवर्क प्रबंधन अभ्यास उचित और गैर-भेदभावपूर्ण है।
- **नर्रितर मूलयांकन:** दूरसंचार उद्योग और OTT प्रदाताओं पर नेट न्यूट्रैलिटी नयिमों के प्रभाव का नयिमति रूप से मूलयांकन कथिा जाए। इस मूलयांकन में इंटरनेट और उसकी सेवाओं की उभरती प्रकृति पर वचार कथिा जाना चाहिये।
- **सार्वजनकि जागरूकता और शकिषा:** नेट न्यूट्रैलिटी के महत्त्व, इसके सदिधांतों और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव के बारे में सार्वजनकि जागरूकता एवं शकिषा बढ़ाई जाए। जागरूक उपभोक्ता नेट न्यूट्रैलिटी के लयिे नयिमों के नर्रिमाण में अहम भूमकिा नभिा सकते हैं।
- **सरवोत्तम वैश्वकि अभ्यास:** सरवोत्तम वैश्वकि अभ्यासों और अन्य देशों में सफल नेट न्यूट्रैलिटी वनियमनों के उदाहरणों से प्रेरणा ग्रहण की जाए। ये भारत के नयामक ढाँचे के लयिे अंतरदृष्टि और सबक प्रदान कर सकते हैं।

नषिकर्ष

भारत में नेट न्यूट्रैलिटी पर सारथक बहस के लयिे एक संतुलित और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सभी हतिधारकों के हतिों पर वचार करे और सुनशिचति करे ककि एक स्वतंत्र एवं खुले इंटरनेट को संरक्षति करने के लयिे नेट न्यूट्रैलिटी के सदिधांतों को बरकरार रखा जाएगा। चूँकि प्रौद्योगकिी का वकिास जारी है, नीतनर्रिमाताओं को सभी के लयिे एक गतशील एवं समावेशी डिजिटल परदृश्य सुनशिचति करते हुए तदनुरूप वनियमनों को अनुकूलति करने के लयिे सत्तर्क बने रहना चाहिये।

अभ्यास प्रश्न: भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के ऐतहिसकि वकिास और महत्त्व पर वचार कीजयिे। नेट न्यूट्रैलिटी वनियमनों से संबधति मूलभूत सदिधांतों और बाधाओं की चरचा कीजयिे तथा देश के भीतर एक सुसंतुलित नयामक ढाँचे के नर्रिमाण हेतु आवश्यक सुझाव दीजयिे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

परश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के “डजिटल इंडिया” योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा क चीन ने कया ।
2. एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जसिसे बड़े आँकड़े एकत्रति करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जा सके कवे हमारी राष्ट्रीय भौगोलकि सीमाओं के भीतर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें ।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से वदियालयों, सार्वजनकि स्थलों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फाई लाना ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनयि :

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/net-neutrality-in-india>

